शिक्षित और समृद्ध प्रदेश के निर्माण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अपने निवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात की।

- 'देश और प्रदेश की उन्नति में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण'
- 'बेटियों के साथ बेटों को भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर प्रदान करेगी राज्य सरकार'

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश की उन्नित में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है तथा राज्य सरकार आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप युवा शक्ति के उन्नयन के साथ शिक्षित और समृद्ध प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात के दौरान सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी का मानना है कि इस देश में युवा, महिला, किसान, गरीब जैसे चार वर्ग हैं, जिनके उत्थान के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण करने से प्राथमिक स्तर पर हमारे बच्चों की नींव मजबूत होगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार बेटियों के साथ बेटों को भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी परिवर्तित बजट में युवाओं के कल्याण तथा सशक्तीकरण के लिए विभिन्न निर्णयों का समावेश किया जाएगा। इस अवसर पर युवाओं ने विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने, रोजगार के लिए विशेष अभियान, खेल सुविधाओं का विस्तार, महिला सुरक्षा, परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने, भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि छात्र संगठनों को युवाओं की समस्याओं को उजागर करने के साथ-साथ उनके समाधान का भी माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ युवा सशक्तिकरण व छात्र कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इससे पहले संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर ध्येय यात्रा पुस्तक भेंट की। इस दौरान राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मौजूद थे।

एक नेता की निजी अदावत का नुकसान उठाया जयपुर कांग्रेस ने

- दो साल से कांग्रेस बनी रही मूकदर्शक, इसका नुकसान कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ा
- चर्चा है कि यह लड़ाई कांग्रेस पार्षदों की नहीं, बल्कि खाचरियावास और मुनेश गुर्जर की है

जयपुर, (का.प्र.)। एक कांग्रेस नेता की निजी आदावत जयपुर शहर की पूरी कांग्रेस को पिछले 2 साल से भारी पड़ रही है और इसका नुकसान न सिर्फ कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ा और आगे आने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को यह नुकसान होना तय है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर को लेकर एक तरह से निजी लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। दूसरी ओर पूरी कांग्रेस 2 साल से इस लड़ाई को तमाशबीन बनकर देख रही है।

यह पूरी कहानी तब से है, जब जयपुर में दो नगर निगम बनाए गए थे। सभी को यह बात याद होगी कि पहले सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र ग्रेटर का हिस्सा बनाया गया था और मालवीय नगर हेरिटेज नगर निगम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उसे समय कैबिनेट मंत्री पद पर रहते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस सीमांकन को बदलवाकर सिविल लाइन को हेरिटेज का हिस्सा बनवाया, तो मालवीय नगर ग्रेटर का हिस्सा बन गया। इसका फायदा यह हुआ कि मुस्लिम वोटर्स के सहारे कांग्रेस का बोर्ड बना, लेकिन मुस्लिम पार्षद 80 प्रतिशत जीतने के बावजूद खुद की ओबीसी महिला को इसलिए महापौर नहीं बनवा पाए, क्योंकि जयपुर के दोनों मुस्लिम विधायक रफीक खान और अमीन कागजी नहीं चाहते थे, कि कोई ओर मुस्लिम नेता जयपुर में उभरे। इसका फायदा यह हुआ कि प्रताप सिंह अपनी खाचरियावास ने सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से जीती मुनेश गुर्जर को महापौर बनवा दिया, लेकिन ऐसे में उप महापौर का पद मुस्लिम के हिस्से गया और प्रताप सिंह खाचरियावास के बेहद नजदीकी पार्षद मनोज मुद्गल उप महापौर बनने से चूक गए।

चर्चा है कि कांग्रेस 2 साल से लगातार इस तमाशे को देख रही है, कि किस तरह से महापौर मुनेश गुर्जर से प्रताप सिंह खाचरियावास के राजनीतिक संबंध बिगड़ने के बाद उन्होंने हर दिन महापौर को हटाने का हर प्रयास किया। जब ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद जब एसीबी ने महापौर के घर छापा मारा और उनके पति की गिरफ्तारी हुई, तो खाचरियावास और उनके साथ ही अमीन कागजी और रफीक खान गुट के पार्षदों की तरफ से इस तरह का दबाव बनाया जाता रहा। हालांकि महापौर दो बार हाईकोर्ट से स्टे लेकर पद पर बैठ गई।

अब एसीबी को महापौर की मिलीभगत के सबूत मिले हैं, लेकिन अभियोजन स्वीकृति सरकार जब तक नहीं देती, तब तक महापौर पद पर बैठी है। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के नेता पहले भी मूकदर्शक थे आज भी सिर्फ नोटिस दिए गए हैं। हालांकि जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आर आर तिवारी ने इस मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और जयपुर के प्रभारी विधायक रोहित बोहरा को स्पष्ट कहा है कि अगर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई, तो पार्टी में अनुशासनहीनता के मामले और बढ़ेंगे।

आपातकाल लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान : मुख्यमंत्री

- 'संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में प्रतिबद्धता' विषयक संगोष्ठी में मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए
- 'प्रबुद्ध वर्ग वंचित तबके को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएं'
- आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की, स्वयं सेवकों को जेल भेजा और चौथे स्तंभ पर लगाया प्रतिबंध : घनश्याम तिवाड़ी

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान और लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले लोग 25 जून 1975 का दिन कभी नहीं भूल सकते। आज जो लोग लोकतंत्र एवं संविधान बचाने का ढोंग कर रहे हैं, उनके द्वारा इस दिन देश में लागू किया गया आपातकाल लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान है।

शर्मा मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में संविधान संरक्षण मंच द्वारा आयोजित 'संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में प्रतिबद्धता' विषयक संगोष्ठी में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार संविधान को सर्वोपरि मानती है। उन्होंने देश के संविधान की रक्षा का अपना वचन बार-बार दोहराया है और प्रदेश में भी संविधान की रक्षा का दायित्व हम पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प समय में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि एक हजार से बढ़ाकर 1150 रुपए करने, किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा कर 8 हजार रुपए करने, 73 लाख परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से आह्वान किया कि वंचित तबके को केन्द्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराएं ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने सम्बोधन में 1975 में तत्कालीन सरकार द्वारा आपातकाल लागू किए जाने से जुड़ी दमनकारी घटनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष के कारण ही देश में पुन: लोकतंत्र बहाली हो सकी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास की भावना के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित वंचित वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। राज्य विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बाबा साहेब ने वंचितों को बराबरी का हक दिलाने के लिए समता का मार्ग दिखाया, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सरसंघचालक डॉ. केशवराव हेडगेवार ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। समता और समरसता दोनों ही आपसी बंधुभाव में निहित हैं।

विधायक रामसहाय वर्मा ने संविधान संरक्षण मंच के द्वारा इस संगोष्ठी के आयोजन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। संगोष्ठी में विधायक, संविधान संरक्षण मंच के पदाधिकारी, वर्तमान एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारीगण और बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आपातकाल की बरसी पर विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी ने युवाओं को कांग्रेस के काले कारनामे बताए। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाडी ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जून 1975 के दिन ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'आपातकाल' की घोषणा की थी। भाजपा आज इस दिन को भारतीय लोकतंत्र में काले दिवस के रूप में मना रही है। जब इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। जेपी आंदोलन अपने चरम पर था। तब इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की स्वीकृति लिए राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर करवाकर देश को जेल की कोठरी के रूप में बदल दिया। लोकतंत्र की हत्या करते हुए इंदिरा गांधी ने सारे नेताओं को जेल में डाल दिया और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। लाखों लोगों को जेल में ठूंस दिया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रतिबंध लगा दिया। इन सब के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। इसके बाद चुनाव हुए और चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज अपने दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 25 जून 1975 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर सभी के मौलिक अधिकारों का हनन किया था। भाजपा आज के दिन को सम्पूर्ण देश में काला दिवस के रूप में मना रही है। यह लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है, आज के दिन लोकतंत्र को रौंदा गया था।

सीकर रोड पर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को 36.88 करोड़ लागत से बन रहे सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट शिलान्यास किया। दिया कुमारी ने कहा कि मानसून में जल-भराव की समस्या से सभी लोग बरसों से परेशान थे, परन्तु आज इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट अब इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल पायेगा।

उन्होने कहा कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट, रेलवे ओवर ब्रिज, बालिका कॉलेज और सेटेलाईट हास्पिटल आ रहे हैं। अन्य जनसमस्याओं की निराकरण के लिए मैं जल्द ही इलाक़े में साप्ताहिक जनसुनवाई शुरु करने जा रही हूँ। सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा होने से भवानी निकेतन, ढेहर के बालाजी, अल्का सिनेमा, 1 नंबर सन एण्ड मून, मुरलीपुरा एवं विद्याधर नगर आदि क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वार्ड नं 4 में दो करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से सर्वोदय कॉलोनी से लालाराम नगर बढारना में जल निकास ड्रेनेज का निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी, समस्त मंडल अध्यक्ष, समस्त वार्ड पार्षद, मोर्चा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल पदाधिकारी, कार्यकर्ता व विद्याधर नगर के सम्मानित जन मौजूद रहे।

विधायक आवास परिसर में सुविधाओं का विस्तार

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को यहां विधायक आवास परिसर में बैंक एटीएम ई-कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता संघ, सरस डेयरी और चिकित्सालय का उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्रीजोगाराम पटेल, डेयरी मंत्रीजोराराम कुमावत, सहकारिता राज्य मंत्री गोतम कुमार, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की मौजूदगी में किया।

देवनानी ने कहा कि विधायक आवास परिसर में लगभग 125 विधायक और उनके परिजन निवास कर रहे हैं। परिसर में यहां के निवासियों की आवश्यकताओं के अनुरुप सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। एसबीआई बैंक एटीएम का ई-कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता संघ का विविध वस्तु भण्डार, सरस डेयरी का पार्लर और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के लिये शहरी स्वास्थ्य केन्द्र का शुभारम्भ किया गया है। भविष्य की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाओं का भी समयानुसार विस्तार किया जायेंगा।

देवनानी ने कहा कि चिकित्सालय में वर्तमान में ऐलोपेथी और होम्योपैथी चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। भविष्य में जरूरत के अनुरूप आयुर्वेद चिकित्सकों की भी यहाँ सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। चिकित्सालय का समय भी आवश्यकतानुसार बढ़ाया जायेगा। परिसर में एक समिति का गठन किया गया है, जो यहां निवास कर रहे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगी। उन्होंने कहा कि परिसर की सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किये गये है। यहां रहने वाले विधायक, उनके परिजन और उनके अतिथि की सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं।

देवनानी ने कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सभी को साथ लेकर चलने के बेहतर प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र के आरम्भ होने से पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात की जायेंगी। आगामी 2 जुलाई को प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक का मकसद है कि सदन नियमों के अनुसार शांतिपूर्ण चलें।

तबादले पर अधिकरण ने रोक लगाई

जयपुर, (का.सं.)। सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत कर्मचारी का तबादला आदेश उसके कार्यग्रहण करने के तीन दिन बाद रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव, सवाई माधोपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और गंगापुर सिटी जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकरण ने पूछा है कि जब तबादला आदेश की पालना में कार्य ग्रहण कर लिया गया तो ट्रांसफर आदेश को रद्द क्यों किया गया। अधिकरण ने यह आदेश देवकी नंदन की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाडा में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था। गत सात मार्च को उसका तबादला यहां से गंगापुर सिटी जिला परिषद में कर दिया।

जयपुर में पीने के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन

- महिलाओं ने सड़क पर धरना दिया
- बदनपुरा पुलिस चौकी का घेराव कर नारेबाजी की

जयपुर। राजधानी में लोग पीने के पानी के लिए परेशान है। मंगलवार को दोपहर बाद चारदीवारी के पास स्थित बासबदनपुरा एरिया की खारवाल बस्ती की महिलाओं ने परेशान होकर बदनपुरा चौकी का घेराव कर दिया और रास्ते पर धरना देकर बैठ गई।

दरअसल, बासबदनपुरा में अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। यहां पीएचईडी की तरफ से टैंकर के जरिए ही पानी सप्लाई होता है। स्थानीय महिला शांति देवी ने बताया कि यहां करीब 100 से ज्यादा परिवार 50 साल से रह रहे हैं। यहां 50 साल से पानी की सप्लाई अब तक शुरू नहीं हुई। कुछ समय पहले सरकार ने यहां लाइन बिछाने का काम शुरू किया तो कुछ जगह लाइन डालने के बाद काम बंद कर दिया। आज भी यहां 100 से ज्यादा परिवार के लोग टैंकर से पानी भरकर अपना गुजर-बसर कर रहे है। आज पानी की सप्लाई नहीं होने से परेशान महिलाएं दोपहर करीब 3 बजे धरने पर बैठ गईं। पुलिस चौकी की सामने दो दर्जन से ज्यादा महिलाएं और पुरूष चौकी के सामने रस्सी लेकर खड़े हो गए और रास्ता बंद कर दिया। इससे ट्रेफिक रूक गया। इस दौरान बारिश शुरू हो गई तो महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई।

विरोध बढ़ता देख जेईएन सुरभि पुलिस चौकी पहुंची। उन्होंने प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आश्वासन दिया कि दो दिन का समय दे विभाग यहां दोबारा लाइन बिछाने का काम शुरू करवा देगा। जेईएन ने बताया कि आप ही में से कुछ लोगों ने विरोध करके यहां काम कर रहे ठेकेदार के कर्मचारियों को भगा दिया था। जेईएन ने बताया कि इस कॉलोनी में 100 मीटर से ज्यादा लम्बाई में लाइन बिछाने का काम शुरू किया था, लेकिन 40 मीटर में लाइन बिछने के बाद लोगों ने ही काम बंद करवा दिया।

साइबर थाने की खिड़की से कूद कर अपराधी भागा

जयपुर। साइबर थाने से सोमवार देर रात एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। जानकारी के अनुसार साइबर ठगी के आरोप में साइबर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। कमरे में पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मी के बाहर आने पर बदमाश खिड़की से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश में जगह-जगह दबिश दी। लेकिन उसका कोई पता नहीं लग सका। इस संबंध में पुलिस ने विधायकपुरी थाने में फरार बदमाश के खिलाफ पुलिस कस्टडी से भागने का मामला दर्ज करवाया है।

साइबर थानाधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि पुलिस कस्टडी से भागने वाला आरोपी दीपक सिंह (21) पुत्र राजेन्द्र सिंह खण्डार सवाई माधोपुर का रहने वाला है। साइबर थाने में दर्ज मामले में आरोपी दीपक सिंह के साइबर फ्रॉड के लिए फेक अकाउंट उपलब्ध करवाने का पता चला था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दबिश देकर आरोपी दीपक सिंह को रविवार शाम गिरफ्तार किया था। पुलिस टीम ने सोमवार दोपहर आरोपी को कोर्ट में पेश कर दो दिन का रिमांड लिया था।

दो स्थानों से सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को हटाया

जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने जोन-9 में गोमती नगर द्वितीय सांगानेर में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बनाई जा रही अवैध दुकान को ध्वस्त किया।

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-7 में ग्राम सिरसी में रोड़ पर सड़क सीमा में आ रहे कब्जा-अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। जोन-9 में गोमती नगर द्वितीय सांगानेर में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बनाई जा रही अवैध दुकान को प्रारम्भिक स्तर पर पूर्णत: ध्वस्त किया गया। साथ ही जोन-14 में ग्राम बिलवा चन्द्रवन के सामने रोड़ सीमा को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा जोन-7 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सिरसी रोड़ पर कब्जा-अतिक्रमण कर कन्टेनर डीपो लगाकर, पत्थर मलवा इत्यादि डालकर किये गये कब्जे-अतिक्रमण को आज जोन-7 में रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-7 स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा जोन-8 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गोमती नगर द्वितीय सांगानेर में अवैध रूप से बेसमेन्ट खोदकर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बनाई जा रही अवैध दुकान को आज जोन-8 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से प्रारम्भिक स्तर पर ही ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-8 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

इसी प्रकार जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बिलवा चन्द्रवन के सामने रोड़ सीमा पर कब्जा-अतिक्रमण कर थड़ी, छप्पर पोष इत्यादि लगाकर किये गये कब्जे-अतिक्रमण को आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-14, 10 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

डी-मार्ट से 1.80 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार झोटवाड़ा जोन की टीम द्वारा सिरसी रोड़ वार्ड नं. 48 स्थित निर्माणाधीन डी-मार्ट से 1 लाख 80 हजार रूपये का जुर्माना राशि वसूल किया। उपायुक्त झोटवाड़ा जोन कमलेश मीना ने बताया कि सिरसी रोड़ वार्ड नं. 48 स्थित डी-मार्ट के निर्माणधीन भवन की निर्माण सामग्री सरकारी भूमि पर डालकर अस्थाई अतिक्रमण किये जाने पर नोटिस जारी किये गये। नोटिस दिये जाने के बाद झोटवाड़ा जोन की संयुक्त टीम ने डी-मार्ट की निर्माणाधीन बिल्डिंग के ठेकेदार और प्रतिनिधि से 1 लाख 80 हजार रूपये की जुर्माना राशि वसूल की।

ग्रेटर निगम 1000 रु. में खरीदेगा ट्री गार्ड, हैरिटेज निगम में 2100 रु. चुकाने की तैयारी!

इस मानसून हैरिटेज निगम 2.66 करोड़ में खरीदेगा 12700 ट्री गार्ड, जबकि ग्रेटर में 74 लाख की लागत से लिए जाएंगे 7400 ट्री गार्ड

-कार्यालय संवाददाता-

- सूत्रों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन ने इस बार भी शर्त यह रखी है कि, जो फ़र्म इन टेंडरों में भाग लेगी, उसे पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में सरकारी विभाग, निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोहे के ट्री गार्ड आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए, जो कि इन टेंडरों की एक तिहाई राशि के बराबर होना चाहिए। जबकि ठेकेदारों का कहना है कि ट्री गार्ड की क्वालिटी देखने के बजाय अधिकारी बेवजह की शर्तें लगाकर चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

जयपुर। हैरिटेज नगर निगम की उद्यान शाखा इन दिनों चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बेवजह करोड़ों रुपए उड़ा रही है। हैरिटेज निगम ने इस मानसून में लगाए जाने वाले पौधों की सुरक्षा के लिए 12700 ट्री गार्ड का टैंडर करीब 2.66 करोड़ रुपए में निकाला है, यानी कि 1 ट्री गार्ड करीब 2100 रुपए में खरीदा जाएगा।

ताज्जुब की बात यह है कि ग्रेटर निगम में भी 7400 ट्री गार्ड लिए जाने है, लेकिन इनकी अनुमानित लागत सिर्फ 74 लाख रुपए रखी गई है, यानी कि एक ट्री गार्ड सिर्फ 1000 रुपए में खरीदा जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जयपुर के दोनों नगर निगम की उद्यान शाखा की कार्यशैली में इतना भारी अंतर क्यों है?

सूत्रों की माने तो हेरिटेज नगर निगम की उद्यान शाखा ने पिछले दिनों हवामहल-आमेर और किशनपोल जोन के लिए 4000, आदर्श नगर के लिए 4500 और सिविल लाइन्स के लिए 4200 ट्री गार्ड खरीदने के लिए निविदा जारी की है। बताया जा रहा हैं कि इन कुल 12700 ट्री गार्ड की अनुमानित लागत करीब 2.66 करोड रुपए रखी गई है। हैरिटेज निगम प्रशासन ने ट्री गार्ड की जो साइज और ऊंचाई तय की है, जिसके अनुसार इसका वजन अनुमानित करीब 16-17 किलो होगा।

वहीं दूसरी ओर ग्रेटर नगर निगम ने जो 7500 ट्री गार्ड मांगे हैं, उनका अनुमानित वजन करीब 9 किलो होगा। खास बात यह है कि ग्रेटर निगम मात्र 1000 रुपए में ट्री गार्ड लेगा, जबकि हैरिटेज निगम करीब 2100 रुपए में।

सूत्रों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन ने इस बार भी अलग शर्त यह रखी है कि, जो फ़र्म इन टेंडरों में भाग लेगी, उसे पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में सरकारी विभाग, निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लोहे के ट्री गार्ड आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए, जो कि इन टेंडरों की एक तिहाई राशि के बराबर होना चाहिए। जबकि ठेकेदारों का कहना है कि ट्री गार्ड की क्वालिटी देखने के बजाय अधिकारी बेवजह की शर्तें लगाकर चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहते है।

चर्चाएं यह है कि अधिकारियों ने यह शर्त उन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए रखी है जो पहले नगर निगम में ट्री गार्ड सप्लाई का काम कर चुके हैं। हैरिटेज सिटी कॉन्ट्रैक्टर्स सोसाइटी समेत करीब आधा दर्जन फर्मों ने इन शर्तों को लेकर निगम प्रशासन के समक्ष आपत्ति भी जताई थी, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

सूत्रों की माने तो ग्रेटर और हैरिटेज निगम पिछले कई वर्षों से ट्री गार्ड की खरीद करता आ रहा है। हर साल करीब 15 से 20 हजार ट्री गार्ड लिए जाते हैं, लेकिन अगला मानसून आते आते यह ट्री गार्ड गायब हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि पार्षदों के अनुशंसा पत्र पर पेड़ और ट्री गार्ड लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाने के कारण इन ट्री-गार्ड का कोई अता-पता नहीं रहता। नियमानुसार उद्यान शाखा के अफसरों को बकायदा रजिस्टर में ट्री गार्ड की एंट्री करनी होती है, लेकिन पिछले कई सालों से यह काम भी बंद हैं।